



नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री



डॉ. मोहन यादव का अभ्युदय मध्यप्रदेश

अभूतपूर्व अधोसंरचना विकास

सड़क नेटवर्क- बेहतर होती कनेक्टिविटी

- वर्ष 2025-26 में 4078 कि.मी. लंबी सड़कों के निर्माण और अगले 5 वर्ष में 1 लाख कि.मी. सड़कों के निर्माण का लक्ष्य
- उज्जैन-जावरा के मध्य 4-लेन ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल्ड हाई-वे निर्माण के लिए ₹5 हजार करोड़ से अधिक की स्वीकृति
- ₹1692 करोड़ की लागत से बनने वाले उज्जैन-इन्दौर 6-लेन मार्ग का भूमिपूजन
- ₹3589 करोड़ की लागत से भोपाल-कानपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर को 4-लेन में अपग्रेड करने की स्वीकृति
- 6-लेन आगरा-ग्वालियर राष्ट्रीय हाई-स्पीड कॉरिडोर परियोजना स्वीकृत
- वर्तमान में ₹ 48,178 करोड़ की 73 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं निर्माणाधीन
- मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत 8565 गांव सड़कों से जुड़े
- मुख्यमंत्री मजरा-टोला सड़क योजना के तहत 20,650 छोटे गांवों में 30,900 कि.मी. पक्की सड़कें बनेंगी, जिसके लिए ₹21,630 करोड़ की स्वीकृति

वायुसेवा और क्षेत्रीय संपर्क



- रीवा, दतिया और सतना हवाई अड्डे का लोकार्पण
- विन्ध्यवासियों को सोगात, रीवा-दिल्ली और रीवा-इंदौर हवाई सेवा प्रारंभ
- उज्जैन हवाई अड्डे के विकास अनुबंध पर हस्ताक्षर
- ग्वालियर से बेंगलुरु, अहमदाबाद, दिल्ली और अयोध्या के लिए वायु सेवा प्रारंभ

रेल और मेट्रो सेवा का विस्तार

- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा प्रदेश के 6 अमृत स्टेशन- शाजापुर, नर्मदापुरम, कटनी साउथ, श्रीधाम, सिवनी और ओरछा का लोकार्पण
- इंदौर में मेट्रो सेवा शुरू, भोपाल में शीघ्र शुरू होगा संचालन
- इंदौर-उज्जैन के मध्य शुरू होगा मेट्रो ट्रेन संचालन
- प्रदेश में बनेगा रेल मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (BEML) को सौंपा गया भूमि आबंटन पत्र। रायसेन के उमरिया में होगी स्थापना

नवीकरणीय ऊर्जा और क्षमता वृद्धि

- मुरैना में पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना ₹ 2.70 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली प्राप्त
- प्रदेश में 2000 मेगावॉट सौर पार्क व 1000 मेगावॉट कंपोजिट ऊर्जा भंडारण परियोजना स्थापित किए जाने की स्वीकृति
- ओंकारेश्वर 278 मेगावॉट फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट से विद्युत उत्पादन प्रारंभ
- 880 मेगावॉट क्षमता की आगर और नीमच सौर परियोजना प्रारंभ
- बिजली उपभोक्ताओं की सुगमता के लिए समाधान योजना प्रारंभ
- उद्योगों सहित सभी गैर-कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन औसतन 10 घंटे बिजली प्रदाय

सिंचाई परियोजनाएं और जल संसाधन

- प्रदेश में लगभग 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र सिंचित। वर्ष 2025-26 तक 65 लाख हेक्टेयर और वर्ष 2028-29 तक 1 करोड़ हेक्टेयर तक सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य
- प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा देश की पहली नदी-जोड़ी केन-बेतवा लिंक परियोजना का भूमिपूजन। पार्वती-कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को लेकर त्रि-पक्षीय समझौता और तापी बेसिन मेगा रीचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ एमओयू
- "पर ड्रॉप मोर क्रॉप" के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 133 वृहद एवं मध्यम प्रेशराइज्ड सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली आधारित परियोजनाएं निर्माणाधीन
- ₹2489 करोड़ से अधिक की लागत से तराया में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय माइक्रो उद्हन सिंचाई परियोजना का लोकार्पण। इससे 100 ग्रामों की 30218 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी
- माइक्रो सिंचाई में मध्यप्रदेश देश में अग्रणी राज्य

विकास और सेवा के 2वर्ष

मध्यप्रदेश अपने बेहतर कल की बुनियाद बना रहा है, जहां सड़क, रेल, हवाई सेवा और ऊर्जा के क्षेत्र में अभूतपूर्व तरक्की हो रही है। विकसित भारत का संकल्प तीव्र विकास, उत्कृष्ट कनेक्टिविटी और पर्याप्त संसाधन से ही संभव होगा। मध्यप्रदेश प्रगति की नई तस्वीर बना रहा है।

- डॉ. मोहन यादव
मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश